भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
(21–22–23 सितम्बर, 2007)
स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे सभागार
पं0 दीनदयाल परिसर (भोपाल)

आतंकवाद पर प्रस्ताव

संप्रग सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण पिछले तीन सालों में भारत विश्व में आतंकवाद के केंद्र के रूप में उभरा है। वर्ष 2004 के बाद से अब तक की आतंकी घटनाओं में अकेले भारत में 3,674 निरपराधों की मौत हुई है। यह संख्या गृहयुद्ध से त्रस्त इराकी हताहतों से थोड़ा कम है। पिछले दस सालों में 53,000 बेकसूर भारतीय आतंकवाद के शिकार हुए हैं। इसकी तुलना में स्वतंत्रता के बाद के युद्धों (कारगिल सहित) में 8,023 भारतीयों की मौत हुई है। आतंकवाद से 13 राज्यों के 156 जिले गंभीर रूप से त्रस्त हैं।

बहुमुखी दानव

भारत में आतंकवाद एक बहुमुखी दानव है। पूर्वोत्तर के कई राज्य हिंसा से ग्रस्त हैं। यहां कई आतंकवादी संगठन अपने–अपने एजेंडे के साथ सक्रिय हैं। आईएसआई द्वारा पोषित ताकतों के घनिष्ठ संपर्क में उल्फा पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य–असम में सक्रिय है। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व कांग्रेस ने इन आतंकवादी संगठनों से मदद ली थी। वर्ष 2005–2006 के दौरान पूर्वोत्तर में करीब 1400 निरपराध नागरिक आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बने।

इस साल जनवरी से लेकर अब तक असम में 50 से अधिक बम विस्फोट हुए, जिनमें से अधिकांश में भीड़भाड़ वाले इलाकों के हिंदी भाषी बाहरी श्रमिकों को निशाना बनाया गया। हिंदी भाषियों पर की जा रही इस हिंसा के माध्यम से आतंकवादी राज्य का जनसांख्यिक स्वरूप बदलने का लक्ष्य रखते हैं। जहां एक ओर अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ अबाधित जारी है, वहीं हिंदी भाषी भारतीयों को खदेड़ भगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कोई ठोस प्रबंध नहीं किया है। वहीं राज्य की सत्ता में बैठे कुछ राजनीतिज्ञों के उल्फा के साथ घनिष्ठ संबंध होने के आरोप लग रहे हैं। अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए राष्ट्रद्रोही ताकतों के प्रति राज्य सरकार के लचर रवैये की भाजपा कड़े शब्दों में निंदा करती है।

जम्मू व कश्मीर

आतंकवाद से संबंधित हिंसा में मारे जाने वालों की संख्या जम्मू व कश्मीर में सर्वाधिक दर्ज की गई है। राज्य में होने वाली आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ छेड़े गए परोक्ष युद्ध का हिस्सा हैं। जनवरी, 2004 के बाद से अब तक आतंकवाद से देश भर में मरने वाले 4000 लोगों में से 40 प्रतिशत मानवीय क्षति जम्मू व कश्मीर में दर्ज हुई। अपने वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए तथाकथित 'सेकुलर दल' राज्य से सेना बहाली घटाने और कुछ अन्य

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

संवेदनशील क्षेत्रों से सेना हटाने की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर सुरक्षा बलों पर लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ताकि उनका मनोबल नीचा किया जा सके।

घाटी में परिस्थितियां निरंतर बिगड़ी हुई हैं। यह बहुत ही खेद की बात है कि अब तक कश्मीरी पंडितों की घरवापसी के लिए उनमें विश्वास पैदा नहीं किया जा सका है। लंबे समय से कश्मीरी पंडित अपने ही देश में निर्वासित जिंदगी गुजार रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि घाटी में चरमपंथियों और पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों का वर्चस्व बना हुआ है।

वामपंथ से खतराः

सीमा पार नेपाल से प्रारंभ होकर माओवादी (नक्सली) हिंसा भारतीय गणराज्य के करीब दर्जन भर राज्यों के 137 जिलों में सक्रिय हैं और देश की सुरक्षा व सभ्य समाज के लिए गंभीर खतरा बन कर उभरे हैं। नक्सली हिंसा के प्रति संप्रग सरकार का नजरिया राष्ट्रहित से निर्देशित न होकर राजनीतिक स्वार्थसाधक है। केंद्र की सत्ता पर आने के बाद संप्रग सरकार ने नक्सली चुनौती से निबटने के लिए राजग सरकार द्वारा गठित केंद्रीयकृत समन्वय नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया।

आंध्रप्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व नक्सलियों के साथ दुरभि संधि कर ली। सत्ता पर आने के बाद कांग्रेसी सरकार ने नक्सलियों के कर्ज को सीजफायर के रूप में चुकाया। नक्सलियों के खिलाफ सभी पुलिस अभियानों को रोककर कांग्रेस सरकार ने उन्हें एकत्रित होने और अपनी शक्ति बढ़ाकर भारतीय गणराज्य व सभ्य समाज पर हमला बोलने का अवसर प्रदान किया गया।

भाजपा शासित छत्तीसगढ़ नक्सली हिंसा का विशेष निशाना है। राज्य सरकार और राज्य के नागरिकों ने 'सलवा जुडुम' के माध्यम से नक्सली उत्पात से निबटने का सराहनीय प्रयास किया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश की वीर जनता को इस प्रयास के लिए बधाई देती है। केंद्र सरकार ने संकुचित राजनीतिक विचारधारा के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को वांछित सहायता देने में कोताही बरती। नक्सली संगठनों ने अब सुरक्षा जवानों और पुलिस चौकियों पर एकसाथ हमला बोलने की रणनीति अपना ली है।

इस्लामी आतंकवाद :

शेष दुनिया के साथ भारत भी वैश्विक इस्लामी आतंकवाद का शिकार है। देश भर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। भारत में आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे नरसंहार में से कुछ के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हैं। किंतु ये भाड़े के विदेशी आतंकवादी अकेले हिंसक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे रहे। स्वाभाविक तौर पर उन्हें स्थानीय मदद मिल रही है। लश्करे तैयबा, जैशे मोहम्मद, और हूजी जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों ने भारत में अपना नेटवर्क स्थापित कर रखा है और बेखौफ अपने रक्तरंजित एजेंडे को निरंतर अंजाम दे रहे हैं।

विगत 25 अगस्त को हैदराबाद में हुए बम विस्फोट में 42 निरपराध मारे गए, 54 गंभीर रूप से घायल हुए। यह 100 दिन से भी कम समय में यह दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। 18 मई को मक्का मस्जिद में किए गए बम विस्फोट में 14 बेकसूरों की जान गई थी। 19 फरवरी को पानीपत के निकट समझौता एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट में 68 जानें गई थीं, हताहतों की संख्या 125 थी। 11 जुलाई, 2006 को मुंबई की ट्रेनों में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों ने 187

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

निरपराधों को लील लिया, करीब 700 गंभीर रूप से घायल हुए। 29 अक्टूबर, 2005 को दिल्ली में 61 नागरिक मारे गए, 90 से ज्यादा घायल हुए। 29 जुलाई, 2005 को वाराणसी में 12 बेकसूर मारे गए, 52 विकलांग हुए। इसके अलावा संकट मोचन, वाराणसी, अयोध्या के रामलला मंदिर, बंगलौर के विज्ञान केंद्र जैसे भारत के सांस्कृतिक स्थलों के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी हमले हुए।

विडंबना यह है कि सरकार आतंकवाद की जड़ों को ही पहचानने से इनकार करती है। वर्तमान सरकार हमारी राजनीति, हमारे प्रजातंत्र और पंथनिरपेक्षता पर मंडरा रहे खतरे की अनदेखी कर रही है। वह आतंकवाद को कुछ गुमराह नवयुवकों की नादानी या ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी खुफिया विभाग द्वारा पोषित व प्रोत्साहित साजिश मानती है, जबकि आतंकवाद की त्रासदी हमारे चारों ओर फैली है। 11 सितंबर को समूचे अमेरिका में विश्व व्यापार टॉवर पर हुए जिहादी हमले में मारे गए 3,000 लोगों की याद में मौन रखा गया। मुंबई की ट्रेनों में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के एक साल गुजर जाने पर भी हमले में मारे गए 187 लोगों की याद में सरकार के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले।

आतंक के खिलाफ कानून

जिहादी खतरे से त्रस्त प्रत्येक देश ने आतंकवाद को प्रारंभिक अवस्था में ही खत्म कर देने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। उन देशों में न केवल आतंकवाद को प्रश्रय देने वालों, बल्कि जिहादी मानसिकता को पोषित करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। पश्चिम के उदारवादी प्रजातांत्रिक देशों में चरमपंथ को बढ़ावा देना दंडनीय अपराध में लाया गया है; कुछ यूरोपीय देशों में प्राणदंड का प्रावधान नहीं होने के कारण ऐसे अपराध के लिए तीस वर्ष तक के कारावास की सजा तय की गई है। अमेरिका ने **'देशभक्त अधिनियम'** (PATRIOT ACT) के कड़े प्रावधानों का अनुपालन किया है। आस्ट्रेलिया से कनाडा तक के प्रजातांत्रिक देशों ने ऐसे ही कड़े कानूनों की व्यवस्था की है।

केवल भारत में ही सरकार ऐसे किसी कानून को बनाने से इनकार करती है। संसद में ऐसे कानून बनाने की मांग को खारिज करते हुए गृहमंत्री उसे 'क्रूर व निष्ठुर' (ड्रेकोनियन) घोषित करते हैं। जिहादियों के शिकार अब स्वयं मुसलमान भी बन रहे हैं, संभवतः सरकार मालेगांव से लेकर हाल के हैदराबाद में मुस्लिम जमावड़े पर किए जा रहे सिलसिलेवार हमलों को पढ़ नहीं पा रही। न तो इन आतंकी वारदातों और न ही हाल के अन्य आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों को पकड़ा जा सका है। वास्तव में हैदराबाद में हुए पहले हमले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें एक मुस्लिम राजनीतिक दल द्वारा अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बताए जाने के बाद रिहा कर दिया गया। एक ही संप्रदाय के छह लोगों, जिनमें से दो को गुजरात के मंडारी बंदरगाह से गिरफ्तार किया गया था, के बारे में आगे कोई पड़ताल नहीं की गई। उन्होंने 24 लाख रुपए हैदराबाद भेजने की जानकारी देते हुए अपना अपराध कबूल किया था। इसके ठीक बाद ही हैदराबाद में दूसरा आतंकी हमला हुआ। मक्का मस्जिद में बम विस्फोट के बाद तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिन्हें राजनीतिक दबाव में छोड़ दिया गया। भाजपा ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था, किंतु सरकार ने सफाई देना जरूरी नहीं समझा।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

एक भी आतंकी हमले की पुख्ता खोजखबर नहीं

संप्रग सरकार के तीन साल के कार्यकाल में एक भी आतंकी हमले की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सका है। यह वर्तमान सरकार के कामकाज का खुलासा करती है। बंगलौर में हुए आतंकी हमले के बाद आंध्रप्रदेश के नालगोंडा जिले में पहुंची पुलिस को क्या सुराग हाथ लगा, जनता को आज तक नहीं बताया गया है। मुंबई की ट्रेनों में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के असली सूत्रधार सकुशल देश से भाग चुके हैं। मालेगांव और हैदराबाद बम धमाकों के पीछे हूजी का हाथ बताया जा रहा है, जो बांग्लादेश से संचालित है। इन घटनाओं के सूत्रधार भी कानून की पकड़ से बाहर हैं। संप्रग सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में सुराग ढूंढ़ने वाली पुलिस को संवेदनशीलता और एहतियात बरतने की हिदायत दी है। इसके कारण ही आतंकी हमला करने वालों की पकड़–धकड़ करने में पुलिस खुद को पंगु महसूस करती है। हैदराबाद में पहला आतंकी हमला करने वालों को रिहा करने और बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के कारण स्थानीय आतंकवाद निरोधी दस्ता खामोश हो गया है।

केरल के चरमपंथी नेता अब्दुल नासेर मदनी, जिसे पूर्ववर्ती सरकारें और अदालतें जमानत पर रिहा करने से भी घबराती थीं, का समर्थन पाने के लिए कांग्रेस और वामदलों में सार्वजनिक होड़ लगी थी। मदनी 1999 के कोयंबटूर बम धमाकों का मुख्य आरोपी है। हाल में साक्ष्यों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया, जबकि उसके अधिकांश सहयोगियों को सजा सुनाई गई है। उत्तरप्रदेश की पूर्व सरकार के मंत्री द्वारा डच कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने का सार्वजनिक फतवा जारी करने के बावजूद संपूर्ण सत्ता अधिष्ठान खामोश था। संसद पर हमले की साजिश रचने के मुख्य सूत्रधार अफजल को मिली मौत की सजा पर केंद्र सरकार कुंडली मारे बैठी है। ऐसे में पुलिस क्या करे? क्या हम आतंकी हमलों के लिए केवल सुरक्षा जवानों पर दोषारोपण करें, जिन्हें किसी समुदाय विषेष से पूछताछ करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देष दिया जाता है? ब्रिटेन में हुए एक आतंकी हमले में एक भारतीय को आस्ट्रेलिया में गिरफ्तार किए जाने से जब स्वयं प्रधानमंत्री को रातभर नींद नहीं आती तो क्या हम पुलिस को शक के आधार पर जांच–पड़ताल करने की मांग कर सकते हैं? आतंकी हमलों में मरने वाले सैकड़ों भारतीयों के लिए क्या कभी प्रधानमंत्री की आंख से आंसू निकले?

हमारा विश्वास है कि आतंक की जड़ों से निबटने और असली कारणों को ढकने की संप्रग सरकार की नीति तथा मौत के सौदागरों के साथ उसकी नरमी ही आतंकवाद से निबटने में इस देश को नाकाम साबित कर रहा है। सभ्य समाज को मौत के सौदागरों के रहमोकरम पर रखने और जिहादियों के प्रति सहानुभूति भाव रखने वाले दोहरे मापदंडों के धनी सेकुलरिस्टों की भाजपा कड़े शब्दों में निंदा करती है।

पोटा का हटाना

सत्ता पर काबिज होते ही पोटा को हटाकर संप्रग सरकार ने नख–दंत विहीन तंत्र का संदेश दे दिया था। सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक–मुसलमानों का मत हासिल करने का प्रयास था। संसद पर हमले के आरोपी की फांसी टालने से लेकर 1993 के मुंबई दंगों से संबंधित श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट तक की कवायद वस्तुतः मुसलमानों को प्रसन्न करना है। यह मुंबई को दहला देने वाले श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के सूत्रधारों को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद नाराज अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने का प्रयास भी है। संप्रग सरकार में शामिल विभिन्न दलों और उसे

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

प्राणवायु देने वाले वामदलों द्वारा आतंकवादियों और चरमपंथियों के महिमामंडन के पीछे उद्देश्य यह है कि जिस जिहादी संत्रास से विश्व त्रस्त है, उसका कटु पक्ष छिपा रहे।

छद्म पंथनिरपेक्ष ताकतों की भूमिका

दुर्भाग्य से बम धमाकों और आतंकी हमलों के पीछे के विभीषक कटु सत्य को छिपाने में इस सरकार को छद्म पंथनिरपेक्ष ताकतों और वामपंथी बुद्धिजीवियों से मदद मिलती है। ऐसे राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी और पत्रकार सदैव न केवल आतंकवाद के प्रति नरमी दिखाते हैं, बल्कि मौत के सौदागरों और जिहादी मानसिकता के बीच घनिष्ठ संबंधों की अनदेखी करते हैं। वस्तुतः छद्म पंथनिरपेक्षी, जिहाद को ईश्वरीय आदेष बताने वाले चारागरों को पोषित और प्रोत्साहित करते हैं।

ऐसा नहीं है कि आतंकी वारदातों में कथित तौर पर गुमराह युवकों की टोली शामिल है। जिहादी आतंक विश्ववापी है और इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, जोर्डन आदि कई मुस्लिम देशों समेत प्रायः सभी देशों ने तेजी से फैलते इस वायरस की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाये हैं। 11 सितंबर को अमेरिकी व्यापार टॉवर पर हमले की वर्षगांठ के आसपास प्रसारित दो ताजा टेपों में 'अल्लाह का हुक्म बजाने के लिए शहीदों के कारवां' का आहवान और ओसामा बिन लादेन द्वारा अमेरिकियों को इस्लाम की शरण में आने या मिट जाने की धमकी महत्वपूर्ण है। अधिकांश मुस्लिम समुदाय ऐसे आहवानों की अनदेखी करता है, यह सबके लिए संतोष का विषय है।

जिहादी आतंक के खिलाफ भारत को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। राजनीतिक दलों और छद्म पंथनिरपेक्षियों द्वारा जिहादी मानसिकता को मिलने वाली सहानुभूति की कुत्सित नीति पर आघात अत्यंत जरूरी है। संप्रग सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान में शामिल होने के लिए विश्व बिरादरी का आहवान करती है, किंतु सरकार में षामिल एक मंत्री बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान अपनी सभाओं में ओसामा के हमषक्ल को साथ लेकर चलते हैं, ताकि अपनी पार्टी के लिए 'अल्पसंख्यकों' का वोट हासिल किया जा सके। सरकार में शामिल किसी भी घटक ने आतंक के खिलाफ सरकार के नजरिए के विरुद्ध काम करने के कारण उक्त मंत्री की खिंचाई नहीं की। वहीं कई राजनीतिक दलों ने संसद पर हमले के मुख्य आरोपी को मिली फांसी की सजा बदलने की मांग की। आतंकवाद के किसी भी आधिकारिक प्रपत्र में आतंकवाद के पुजारी ओसामा बिन लादेन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

वामदलों की भूमिका

अन्य खतरा वामदलों से है। इस सरकार के प्राणदाता वामपंथी भारत की विदेश नीति को, खासकर फलीस्तीन और इरान मामलों में इस्लामी चरमपंथ का समर्थक बनाना चाहते हैं। संप्रग सरकार को इजराइल से दूर रखने के अपने मुहिम में वामपंथी, फीलीस्तीनी अधिकारियों से भी ज्यादा कट्टर इस्लामी होने का सबूत देते हैं। दूसरी ओर, चरमपंथी संगठन–हमास द्वारा बाधित शांति प्रक्रिया को दुबारा रास्ते पर लाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रपति और इजराइली प्रधानमंत्री द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

आतंकवाद से लड़ने में सरकार द्वारा विश्व बिरादरी को दिए जा रहे संदेश और दूसरी ओर जिहादी जुनून को पोषित करने वालों को दिए जा रहे समर्थन से पैदा विरोधाभास के कारण ही आतंक निरोधी योजना के क्रियान्वयन में प्रशासन भ्रमित है। सरकार के नरम रुख और आतंकी

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

सूत्रों पर कड़ाई किए जाने से मनाही के कारण इस बात में दो राय नहीं कि भविष्य में इस देश के कई अन्य भाग भी ऐसे ही लहूलुहान होते रहेंगे।

सभ्य समाज की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल, खासकर पुलिस ही मुख्य तंत्र है, जो मजहबी जुनून से लैस और विशेष लक्ष्य के लिए आधुनिक अस्त्र–शस्त्र से प्रशिक्षित जिहादियों का सामना करती है। इस निराशाजनक परिस्थिति में पुलिस इन हिंसक तत्वों से दो–दो हाथ करने में सक्षम नहीं है। आतंरिक सुरक्षा पर गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट कहती है, ''ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा राज्य पुलिस बलों के रहन–सहन और कार्य के माहौल के अध्ययन से चौंकाने वाली तस्वीर उभरती है।'' रिपोर्ट कहती है, ''25 प्रतिशत पुलिस स्टेशन और 50 प्रतिशत बाहरी पुलिस चौकियों में भवन नहीं हैं। 37 प्रतिशत से अधिक पुलिस जिले अस्थायी शिविरों से संचालित हैं। 70 प्रतिशत से अधिक पुलिस जिलों में सुचारू कंट्रोल रूम नहीं हैं। 34 प्रतिशत पुलिस जिलों में पुलिस निरीक्षकों के पास सरकारी निवास नहीं है। 70 प्रतिशत कांस्टेबल्स के पास रिहायश की सुविधा नहीं है। 43 प्रतिशत भारतीय पुलिस के पास आवागमन के साधन नहीं हैं।'' रिपोर्ट आगे कहती है, ''अधिकतर मामलों में साइकिल ही माध्यम है।''

रिपोर्ट आगे कहती है, ''पुलिस के पास मौजूद शस्त्र पुराने और कारगर नहीं हैं।'' उनके प्रशिक्षण के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है, ''पुलिस बजट का केवल एक प्रतिशत आतंकवादियों द्वारा अपनाई जा रही नई तकनीक और अपराध के प्रशिक्षण पर खर्च होता है।'' संचार माध्यमों के बारे में रिपोर्ट कहती है, ''जितना कम कहा जाए, उतना अच्छा है।''

इस तरह हम कठिन परिस्थितियों से घिरे हैं। आतंकवाद के *दानवावतारों*– नक्सल, उल्फा या जिहादी– ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। वे प्रत्यक्ष रूप से पृथक, किंतु परोक्ष रूप से साथ–साथ भारत के खिलाफ हिंसा में संलग्न हैं।

केंद्र और अधिकांश राज्यों का सत्ता अधिष्ठान अवसरवादी कुत्सित मानसिकता से ग्रस्त है। क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने में भी गुरेज नहीं है। आतंकवाद से निपटने में लगे सुरक्षा बल को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें आतंकवादियों के समर्थन में जुटा राजनीतिक हस्तक्षेप भी शामिल है। भाजपा केंद्र सरकार से मांग करती है कि वह आंतरिक सुरक्षा पर गठित टास्क फोर्स की प्राप्तियों और संस्तुतियों के आलोक में सुरक्षा बल को पर्याप्त संसाधन जुटाए।

भाजपा वर्तमान सत्ता अधिष्ठान के चाल, चरित्र व चिंतन को देखते हुए आश्वस्त है कि संप्रग सरकार आतंकवाद की चुनौती का सामना करने में नाकाम है। बढ़ते आतंकवादी कहर की रोकथाम के लिए संप्रग सरकार की अब तक की कार्रवाइयां गौण हैं। भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए नकारात्मक एजेंडे के साथ बेसुरा व अवसरवादी गठबंधन करने वाली सरकार सुप्रषिक्षित विदेशी आतंकवादी संगठनों पर अंकुश लगा पाने में सक्षम नहीं है। इस युद्ध को जीतने के लिए 'शून्य सहिष्णुता' (ZERO TOLERANCE) की नीति अपनाने की जरूरत है। संप्रग सरकार यह नहीं कर सकती। समय आ गया है कि अब संप्रग सरकार और उसका रिमोट कंट्रोल बने वामपंथियों को सत्ता से उतार फेंका जाए।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com